


| | | |
|---|---|--|
|  सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | फाल्गुन 21, बुधवार, शाके 1946- मार्च 12, 2025 <i>Phalguna 21, Wednesday, Saka 1946- March 12, 2025</i> | |

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 20, 2025

जी.एस.आर.120 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) (पहला संशोधन) नियम, 2025 है।
- ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची VI में, सारणी में क्रम संख्यांक (4) पर आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "परिनिंदा- परिनिंदा के प्रत्येक आदेश की शास्ति के लिए, एमएसीपी एक वर्ष के लिए आस्थगित की जायेगी।" हटायी जायेगी।

टिप्पणी:- इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व देय एसीपी/एमएसीपी के मामले तत्कालीन उपबंध द्वारा शासित होंगे।

[सं. एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश से,

देबाशीष पृष्ठी,

प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)।

**FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
NOTIFICATION
Jaipur, January 20, 2025**

G.S.R.120 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) (First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with immediate effect.

(3) In Schedule VI of the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, the existing expression as appearing at S.No. (4) in the table "Censure - MACP will be deferred for one year for penalty of each order of censure.", shall be deleted.

Note: - The cases of ACP/MACP due before issuance of this notification, shall be governed by the then provision.

[No. F.15(1)FD/Rules/2017 Pt.]

By order of the Governor,

Debasish Prusty,
**Principal Secretary to the Government,
Finance (Budget).**

Government Central Press, Jaipur.